राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत सामुदायिक प्रबंधन में लिफ्ट सिंचाई योजना की गाथा :–

आराधना पटनायक,
भा0प्र0से0
उपायुक्त, लोहरदगा।

पृष्ठ भूमि

पूर्व की लिफ्ट सिंचाई योजना मूलतः विधुत आधारित थी। कुछेक स्थलों पर भारी डीजल मशीन (14 एच0पी0) का प्रयोग होता था। सिंचाई कूप पूर्णतः व्यक्तिगत थे तथा कई व्यक्तिगत

पम्प सेटों (किरासन/ डीजल चालित) का प्रयोग हो रहा था तथा जबकि स्थलों पर सतही बहाव वाले सफल चेक डेम भी थे। परन्तु अनियमित विधुत आपूर्ति के कारण यह अधिक कारगर नहीं थे। वही जिला का मात्रा 70 ग्राम (20प्र) ही विधुतिकृत था। निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना में जन सहभागिता का अभाव था। डीजल चालित लिफ्ट सिंचाई अपने अत्यधिक लागत एवं रख–रखाव की समुचित व्यवस्था के अभाव में अलाभकारी साबित हो रहे थे, जिसमें भारी मशीन एवं लोहे के पाईप के अवरोध के कारण अत्यधिक डीजल खपत होता था। व्यक्तिगत सिंचाई कूप एंव पम्पसेट यद्यपि सफल थे परन्तु लागत अधिक आता था। फलस्वरूप अभी तक एक एकड़ पटवन व्यवस्था हेतु 30,000/– रू0 पूँजीगत व्यय करना पड़ता था।

कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्त्तन का मूल आधार सिंचाई क्रांति ही हो सकता था। अतः राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत दो पहलुओं पर एक साथ कार्यारम्भ किया गया।

1. भुगर्भीय जल स्तर में सुधार एवं निरर्थक बह जाने वाले जलों के संग्रहण हेतु श्रृंखला में छोटे/ मध्य आकार के चेक डेम एवं जल संवर्द्धक तालाबों का निर्माण।
2. पठारी निम्न श्रोत से उपरी कृषि क्षेत्रा में जल के उद्भव हेतु कम लागत वाले 5 से 8 हॉर्स पावर के डीजल चालित पम्पसेट जिसके साथ न्यूनतम अवरोध वाले पी0भी0सी0 पाईप द्वारा आवश्यक स्थलों तक जल पहुँचाने की व्यवस्था हो।

कार्य का प्रबंधन :–

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत जन सहभागिता एवं अंशदान के साथ जल उपभोक्ता समिति के माध्यम से लिफ्ट सिंचाई योजना की स्थापना को एक अभियान के रूप में वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक लिफ्ट के कमान्ड क्षेत्रा से संबंधित सभी कृषकों को जल उपभोक्ता समिति का सदस्य बनाया गया तथा उनके स्थानीय ज्ञान के मद्द से स्थलों का चयन किया गया । सभी सदस्यों द्वारा प्रत्येक योजना में कुछ लागत तथा श्रम के रूप में अंशदान लगाया गया। जो समिति के सदस्यों की योजना में रूचि एवं स्वामित्व एहसास को जाहिर करने के लिए आवश्यक था। योजना पूर्ण होने के पश्चात् इस समिति द्वारा सिंचाई सुविधा हेतु प्रति घंटा 12 रू0 से 15 रू0 शुल्क के रूप जमा करने की व्यवस्था की गई। इससे सृजित निधि द्वारा प्रत्येक लिफ्ट के संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया। जल उपभोक्ता समिति द्वारा अपने सप्ताहिक बैठक में योजना के बेहत्तर लाभ की कार्य योजना, दायित्व की हिस्सेदारी, लेखा संधारण व्यवस्था तथा अन्य प्रासंगिक समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालना प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए योजना क्रियान्वयन से पूर्व ही विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से लाभुकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

उपलब्धि :–

उक्त सामुदायिक व्यवस्था के तहत् कुल 107 लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई ताकि चेक डेम सिंचाई कूप एवं बडे डब्लू0एस0टी के माध्यम् से संग्रहित जल को खेत तक पहुँचाया जा सके।

विवरणी निम्नवत् है :–

स्वीकृत ईकाई	पूर्ण ईकाई	परियोजना लागत		
		RSVY मद से अनुदान	जल उपभोक्ता समिति का अंशदान	कुल लागत
1	*2*	*3*	*4*	*5*
107	74	218.38	26.54	244.72

उक्त ईकाई से लगभग 1250 हे0 को सिंचित किया जाना संभव हो सकेगा। जो जिले के सिंचाई व्यवस्था हेतु मील का पत्थर साबित होगा।

सफलता के कुछेक दृ टान्त :–

- ## डाड़ू महतो टोली :–

सेन्हा प्रखण्ड के चितरी पंचायत की जनजातियें बहुल्य इस ग्राम में दक्षिण कायेल नदी पर दिसम्बर 2004 में लिफ्ट सिंचाई की स्थापना की गई। ग्रामीणों द्वारा ''हरित क्रान्ति लिफ्ट सिंचाई समिति'' नामक जल उपभोक्ता समिति का गठन कर रख–रखाव प्रारम्भ किया गया। समिति के नवयुवक ग्रामीणों का चयन कर पम्प सेट एवं मोटर के रख–रखाव का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम वर्ष 30 कृषकों ने अन्तप्रेरणा से 12 हेक्टेयर भूमि पर रबी की सफलतापूर्वक खेती किया गया। जिससे प्रेरित होकर दूसरे वर्ष 40 कृषकों ने 22 हे0 भूमि पर रबी फसल का लाभ लिया। आज इस सिंचाई व्यवस्था से हरित क्रान्ति लिफ्ट सिंचाई समिति के सभी सदस्य 12000/– रु0 से अधिक अतिरिक्त आय अर्जित कर रहें हैं तथा इसे और लाभोत्पादक बनाने हेतु नकदी एवं औषधीय फसलों की खेती प्रारम्भ कर रहें हैं। इस ग्राम की प्रेरक हरियाली की सफलता को सहारा समाचार चैनल द्वारा 21 फरवरी 2006 एवं 22 फरवरी 2006 के प्रसारण में भी दर्शाया गया है।

- **भडगॉव** :– लोहरदगा प्रखण्ड के हिरही पंचायत के जनजातिये बहुल्य इस ग्राम की बहुसंख्यक आबादी मुख्यतः मजदूरी कार्य पर निर्भर थी। सिंचाई सुविधा के अभाव में कृषि कार्य घाटे का कार्य थ। अतः सिंचाई विस्तार हेतु अक्टूबर 2005 में जनसहभागिता से लिफ्ट सिंचई योजना की स्थापना की गई। पहलीबार 45 कृषकों द्वारा 20 हे0 भूमि पर रबी की खेती की गई। आज सभी कृषक अपनी आवश्यकता हेतु प्रर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित कर रहें हैं और खेती

को अधिक लाभोत्पादक बनाने हेतु सब्जी एवं नकदी फसल की खेती प्रारम्भ करने की योजना बना रहें हैं। चालू वर्ष में गेहूँ की बिक्री दर ऊँची रहने के कारण इनके द्वारा अतिरिक्त उत्पादित फसल का इन्हें अच्छा लाभ मिला है। खेती हेतु आवश्यक ऋण व्यवस्था स्वयं सहायता समूह के आंतरिक संसाधनों से किया जा रहा है जिससे इनके आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है। अब वे खेती के साथ–साथ अतिरिक्त भूमि पर फलदार वृक्षारोपण भी प्रारम्भ कर दियें हैं। जिससे जल्द ही अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

- जवाल :– सेन्हा के पहाडी क्षेत्रा में अवस्थित पूर्णतः जनजातिये आबादी वाले इस ग्राम में

केवल वर्षा आधारित धान की खेती की जाती थी। जिसका अनावृष्टि से प्रभावित रहने के कारण अधिकांश ग्रामीण जाड़े के दिनों में जीवन निर्वाह हेतु पलायन कर जाते थे। इस ग्राम में फरवरी 2006 में दो लिफ्ट सिंचाई योजना स्थापित किया गया जिससे 42 कृषकों ने सफलता पूर्वक रबी की खेती की और यह प्रयास जिले के दुर्गम क्षेत्रों के अन्य ग्रामों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप दुर्गम पहाडी क्षेत्रों से लिफ्ट सिंचाई

योजना की स्थापना की मांग कृषकों द्वारा किया जा रहा है।

आज 74 लिफ्ट सिंचाई योजना से 700 हेक्ट0 नवसृजित क्षेत्रा विस्तार में सफलता पूर्वक गेहूँ, सरसो, मटर, आलू एवं दलहन की खेती की जा रही है और 1700 परिवार नियमित रूप से रबी की खेती का लाभ ले रहें है। 88 जल उपभोक्ता समिति गठित है तथा 74 ऑपरेटर को लिफ्ट सिंचाई योजना के बेहत्तर रख–रखाव एवं संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। जन सहभागिता से संचालित इस सिंचाई व्यवस्था का अत्यन्त ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। जिसने पूर्व की लिफ्ट सिंचाई योजना की असफलता संबंधी भ्रम को समाप्त कर दिया है। जिले के पठारी टोपोग्राफी के कारण सिंचाई हेतु विकल्प अत्यन्त सिमित है, फलस्वरूप अन्य ग्रामों में भी लिफ्ट हेतु निरन्तर मांग किया जा रहा है।

लिफ्ट सिंचाई योजना के सफलताओं ने निर्धन एवं लघु कृषकों को अपने खाद्यान्न उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का नया मार्ग दिखाया है। कृषक सुनिश्चित खरीफ फसल के साथ–साथ रबी की खेती का भी लाभ ले रहें हैं। चेक डेम एवं लिफ्ट व्यवस्था के संयुक्त प्रयास से जिले के फसल पद्धति में बदलाव दृष्टिगोचर होने लगा है और कृषकों का एक बड़ा तबका नकदी एवं औषधीय लाभदायक खेती हेतु अग्रसर हो रहा है। यह बदलाव निःसन्देह ग्रामीण जीवन के उत्थान में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

---------------------- XXXX ----------------------